दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार 02 फरवरी 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 126

महत्वपूर्ण एवं खास

60 लाख नई नौकरियां व गरीबों को 80 लाख घर देंगे

नईदिल्ली (आरएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट आज पेश किया। सीतारमण ने 2019 में अपना पहला बजट पेश किया था। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट में विकास को प्रोत्साहन दिया गया है। साथ ही इस बजट में सरकार के इरादे को दर्शाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48 हजार करोड़ रुपये का फंड रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले पांच सालों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता रखी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया गया है। ये बजट डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। एनपीए से निपटने के लिए बैड बैंक बनाया गया है। पीएम गति शक्ति में ग्रोथ के सात इंजन हैं। इसकी मदद से पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी मिलेगी। यही नहीं पीएम गति शक्ति से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में देश के नागरिकों के विकास पर जोर दिया गया है। साथ ही मध्यम वर्ग के लिए बेहतर माहौल बनाने पर जोर दिया गया है। इस बजट में अगले 25 सालों की नींव रखी गई है।

अभिनेत्री शबाना आजमी कोरोना वायरस से संक्रमित

मुंबई (आरएनएस)। जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी ने मंगलवार को बताया कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं और इस समय पृथक-वास में हैं। 71 वर्षीय अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ''मैं आज कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हूं। मैंने स्वयं को घर में पृथक-वास में रखा है और मैं, मेरे निकट संपर्क में आए सभी लोगों से कोविड जांच कराने का अनुरोध करती हूं।'' शबाना आजमी करण जौहर निर्देशित फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में नजर आएंगी। इस फिल्म में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, धर्मेंद्र और जया बच्चन भी अभिनय कर रहे हैं। इसके अलावा शबाना आजमी पैरामाउंट प्लस की सीरीज 'हालो' में भी दिखाई देंगी। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने बताया कि मुंबई में सोमवार को कोविड-19 के 960 नए मामले सामने आए तथा 11 और संक्रमितों की मौत हो गई।

केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेंसी 'डिजिटल रुपी' लागू करने की घोषणा

नईदिल्ली(आरएनएस)। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए डिजिटल रुपी लागू करने की घोषणा की, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 से आरंभ किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) डिजिटल अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से बढ़ावा देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल करेंसी से एक और अधिक दक्ष तथा सस्ती करेंसी प्रबंधन व्यवस्था देखने में आएगी। डिजिटल करेंसी ब्लॉक चेन तथा अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेगी। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल के वर्षों में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतानों एवं फिनटेक नवोन्मेषणों का देश में तेज गति से विकास हुआ है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ उपभोक्ता अनुकूल तरीके से देश के प्रत्येक क्षेत्र में पहुंच सके, इन क्षेत्रों को नियमित रूप से प्रोत्साहित कर रही है। इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए और अपनी स्वतंत्रता का 75 वर्ष मनाते हुए यह प्रस्तावित किया गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयूएस) की स्थापना की जाएगी।

अमेरिका में दो लोगों पर राष्ट्रपति को जान से मारने की धमकियां देने का आरोप

कॉलेज पार्क (अमेरिका) । अमेरिका में मैरीलैंड और कंसास के एक-एक व्यक्ति पर राष्ट्रपति जो बाइडन को जान से मारने की अलग-अलग धमकियां देने का आरोप लगाया गया है। प्राधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। मैरीलैंड के रयान मैथ्यू कॉनलन (37) और कंसास के स्कॉट रयान मैरीमैन (37) को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। कॉनलन पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकियां देने का भी आरोप लगाया गया है। संघीय प्राधिकारियों ने बताया कि मैरीमैन ने पिछले मंगलवार को अपने गृहनगर में पुलिस को फोन किया और कहा कि वह राष्ट्रपति से मिलने के लिए वाशिंगटन डीसी जा रहा है। जब खुफिया सेवा के एक एजेंट ने उसे गत बुधवार को बुलाया तो मैरीमैन ने कहा कि ईश्वर में उसे वाशिंगटन जाकर ''एक नाग का सिर काटने' के लिए कहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया देश का आम बजट 2022-23

- टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
- घटा कॉरपोरेट टैक्स
- डिजीटल करेंसी होगी लांच
- 16 लाख नौकरियों का वादा

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में देश का आम बजट 2022-23 पेश किया। जो कि 39.45 लाख करोड़ का आम बजट है। हालांकी इस आम बजट से मध्यम वर्ग को निराशा ही हुई है क्योंकि बजट में टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अपने बजट भाषण में सीतारमण ने आयकर स्लैब पर कोई बात नहीं की जिसका सीधा मतलब यह है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा क्रिप्टोकरंसी से होने वाली इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगा दिया गया है। वहीं कॉरपोरेट टैक्स 18 से घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है। सीतारमण ने बजट में 16 लाख नौकरियां देने का भी वादा किया है। वित्त मंत्री के बजट पेश करने के बाद लोकसभा कल तक के लिये स्थगित कर दी गयी है। 2022-23 से डिजिटल रुपया लांच करने की भी घोषणा की गयी। वित्त मंत्री ने कहा कहा कि आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री सीतारमण का भी यह चौथा बजट है.

वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना डिजिटल करंसी लॉन्च करेगा. सरकार ने कहा कि रिजर्व बैंक अपना डिजिटल रूपी लॉन्च करेगा. ऐसी खबर पहले से थी कि सरकार क्रिप्टोकरंसी पर कोई सधा हुआ रुख अपनाएगी. हालांकि बजट से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में क्रिप्टोकरंसी पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बाद में प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने कहा कि सरकार क्रिप्टोकरंसी पर नपा-तुला और सधा हुआ रुख अपनाएगी.

इससे साफ हो गया कि सरकार बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी, लेकिन क्या उसे वैध किया जाएगा, इस पर अभी असमंजस बना हुआ है. वित्त मंत्री ने बजट में साफ कर दिया कि रिजर्व बैंक अपना डिजिटल करंसी लेकर आएगा जिसे डिजिटल रुपी कहा जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा. गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.

यह बजट कोरोना महामारी के दौर में पेश हुआ है. इसलिए, इसका महत्व बढ़ जाता है. बजट के बाद सभी लोगों के दिमाग में सवाल है कि इससे क्या सस्ता और महंगा होगा. बजट के बाद खेती का सामान सस्ता होगा. इसके अलावा बजट में कट और पॉलिश्ड डायमंड पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है. यानी ये भी सस्ते हो जाएंगे. वहीं, छाते खरीदना महंगा हो जाएगा. छातों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया गया है.

ये चीजें हुईं सस्ती

जूते-चप्पल, ज्वैलरी, इलेक्ट्रिक सामान, विदेशी मशीनें, कृषि उपकरण, मोबाइल चार्जर, मोबाइल, कपड़े,चमड़े का सामान।

यह हुई महंगी

छाता, शराब, कॉटन, खाद्य तेल, एलईडी लाइट, मोबाइल फोन चार्जर के ट्रांसफार्मर और कैमरा लेंस पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है. घरेलू मोबाइल फोन चार्जर होंगे सस्ते. देश में असेंबल होने वाले मोबाइल भी सस्ते हो सकते हैं. घरेलू स्तर पर मोबाइल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.

इसके अलावा वित्त मंत्री सीतारमण ने कुछ कैमिकल्स पर कस्टम ड्यूटी घटाने का भी प्रस्ताव किया है. इनमें मिथेनॉल भी शामिल है. उन्होंने कहा कि ऐसा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है. वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी की छूट को एक और साल के लिए बढ़ाया जा रहा है.

सीतारमण ने कहा कि 400 नए जनरेशन वाली वंदे भारत ट्रेनें बेहतर क्षमता के साथ अगले तीन सालों में लाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल अगले तीन सालों में विकसित किए जाएंगे. और मेट्रो सिस्टम को विकसित करने के लिए इनोवेटिव तरीकों को लागू किया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले पांच सालों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता रखी गई है.

एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हुआ

- निलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के लिए रणनीतिक भागीदार चयनित
- एलआईसी का सार्वजनिक निर्गम जल्द आने की उम्मीद

नईदिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा, 'नई सार्वजनिक उपक्रम नीति को लागू करने के लिए एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हुआ।' उन्होंने कहा कि एनआईएनएल (निलाचल इस्पात निगम लिमिटेड) के लिए रणनीतिक भागीदार का चयन कर लिया गया है। इसके अलावा एलआईसी का सार्वजनिक निर्गम जल्द ही आने की उम्मीद है। वर्ष 2022-23 में अन्य के लिए भी प्रक्रियाएं शुरू हो सकती है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफीड) और राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी ने अपना कार्य शुरू कर दिया है।

कॉरपोरेट निकासी को गति- श्रीमती सीतारमण ने कहा कि नई कंपनियों के पंजीकरण को गति देने के लिए कई आईटी आधारित प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों को स्वैच्छिक तौर पर बंद करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रि-इंजनियरिंग प्रक्रिया के साथ सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सलेरेटिड कॉरपोरेट एग्जिट (सी-पेस) की स्थापना की जाएगी। इसके जरिये कंपनियों को बंद करने में लगने वाला समय दो वर्षों से घटकर छह महीने रह जाएगा।

ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता - वित्त मंत्री ने आगे कहा कि समाधान प्रक्रिया की बेहतर कुशलता और सीमापार दिवालिया समाधान की सुविधा प्रदान करने के लिए ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

एमएसपी के तहत मिलेंगे 2.7 लाख करोड़ रुपये; ड्रोन के जरिए मदद पहुंचाएगी सरकार

- किसानों को वित्त मंत्री का बड़ा तोहफा

नईदिल्ली (आरएनएस)। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री ने आज पेश हुए बजट में ऐलान किया कि सरकार अगले वित्त वर्ष में किसानों को एमएसपी के तहत 2.7 लाख करोड़ रुपये देगी। कृषि सेक्टर को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने ये कदम उठाया है। इस बजट से देशभर के किसानों को उनके फसल की सही कीमत देने में मदद मिलेगी।

साथ ही सरकार ने ड्रोन की मदद से किसानों को मदद पहुंचाने का फैसला किया है। सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से फसलों का बेहतर प्लानिंग, जमीन का रिकॉर्ड समेत कई काम ड्रोन से कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही फल, सब्जी के किसानों को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए अलग से बजट आवंटन का ऐलान किया है।

सरकार के इस कदम से उम्मीद है कि किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा और वो उपज बढ़ाने में बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे 24 जनवरी को आए आंकड़ों के अनुसार केंद्र ने चालू मार्केटिंग सेशन 2021-22 में अब तक 606.19 लाख टन धान की खरीद की है। धान की सबसे अधिक खरीद पंजाब से हुई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''अब तक लगभग 77 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मूल्य का 1,18,812.56 करोड़ रुपये का लाभ मिला है।''

कल पेश हुई आर्थिक समीक्षा 2021-22 में कहा गया कि कृषि क्षेत्र ने कोविड-19 के झटके को सहने के प्रति अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया है और इसके चालू वित्तवर्ष में 3.9 प्रतिशत की दर से बढने का अनुमान है। समीक्षा में सरकार को फसल विविधीकरण, संबद्ध कृषि क्षेत्रों और नैनो यूरिया जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया है।

आर्थिक समीक्षा 2021-22 ने ड्रोन जैसी नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाने के अलावा कृषि अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) तथा जैविक खेती को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। समीक्षा में कहा गया है, ''कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने कोविड-19 के झटके के प्रति जिजीविषा को प्रदर्शित किया है ज्पशुधन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि, इस क्षेत्र में समग्र विकास के प्रमुख चालक रहे हैं।''पिछले दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। समीक्षा में कहा गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान इसके 3।9 प्रतिशत की दर से बढने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष में 3.6 प्रतिशत था।

भारतीय रिजर्व बैंक 2022-23 से डिजिटल रुपी जारी करेगा

- अवसंरचना की समन्वित सूची में डाटा सेंटर तथा ऊर्जा भंडारण प्रणालियां शामिल की जाएंगी
- विशेषज्ञ समिति वेंचर कैपिटल तथा निजी इक्विटी निवेश में वृद्धि का अध्ययन करेगी
- पिछले वर्ष वेंचर कैपिटल तथा निजी इक्विटी द्वारा 5.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया

नईदिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए ब्लॉक चेन तथा अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए डिजिटल रुपी लागू करने का प्रस्ताव रखा, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 से जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि

केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) डिजिटल अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि 'डिजिटल करेंसी से और अधिक दक्ष और किफायती करेंसी प्रबंधन प्रणाली का निर्माण होगा।'

उन्होंने देश में निवेश तथा ऋण उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अन्य पहलों का भी प्रस्ताव रखा।

अवसंरचना स्थिति -श्रीमती सीतारमण ने प्रस्ताव रखा कि डेंस चार्जिंग अवसंरचना तथा ग्रिड-स्केल बैट्री प्रणालियों सहित डाटा केन्द्रों तथा ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को अवसंरचना की समन्वित सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ''इससे डिजिटल अवसंरचना तथा स्वच्छ ऊर्जा भंडारण के लिए ऋण उपलब्धता की सुविधा प्राप्त होगी।''

वेंचर कैपिटल तथा निजी इक्विटी निवेश

वित्त मंत्री ने वेंटर कैपिटल तथा निजी इक्विटी निवेश में तेजी लाने की जांच करने तथा उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वेंटर कैपिटल तथा निजी इक्विटी ने सबसे बड़े स्टार्टअप तथा विकास परितंत्रों में से एक को सुगम बनाते हुए पिछले वर्ष 5.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया। उन्होंने कहा, 'इस निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियामकीय तथा अन्य बाधाओं की समग्र जांच करने की आवश्यकता है।'

मिश्रित वित्त - श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार समर्थित फंड एनआईआईएफ तथा सिडबी फंडों के फंड ने स्केल पूंजी उपलब्ध कराई थी, जिसका बहुगुणक प्रभाव पड़ा था। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट एक्शन, डीप-टेक, डिजिटल अर्थव्यवस्था, फार्मा तथा एग्री-टेक जैसे महत्वपूर्ण सनराइज सेक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार मिश्रित वित्त के लिए थीमेटिक फंड को बढ़ावा देगी, जिसमें सरकार का हिस्सा 20 प्रतिशत तक सीमित रहेगा तथा फंड निजी फंड मैनेजरों द्वारा प्रबंधित किये जाएंगे।

अवसंरचना परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता - वित्त मंत्री ने कहा कि अवसंरचना आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए, बहुस्तरीय एजेंसियों से तकनीकी तथा ज्ञान सहायता के साथ पीपीपी सहित परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय व्यवहार्यता में वृद्धि वैश्विक सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों के अनुपालन, वित्त पोषण के नवोन्मेषी तरीकों तथा संतुलित जोखिम आवंटन द्वारा की जाएगी।

हवा की रफ्तार से दौड़ेगी रेलवे! तीन वर्ष में 400 वंदेभारत ट्रेनें चलेंगी

- नेशनल हाईवे की लंबाई भी बढ़ाई जाएगी

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। इस बजट में कहा गया कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। दावा है कि इस बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है। इसी बीच निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अगले 3 सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी। दरअसल, अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी। इसके साथ अगले तीन सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। साथ ही 8 नई रोपवे का निर्माण होगा। वंदे भारत ट्रेनें देश की पहली स्वदेशी तकनीक से निर्मित होने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 किमी तक बढ़ाया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों के पर्वतमाला रोड को पीपीपी मोड्स पर लाया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस ट्रेन में ऑन बोर्ड वाई-फाई, जीपीएस आधारित यात्री इन्फॉर्मेशन सिस्टम, खूबसूरत आंतरिक सजावट, वैक्यूम शौचालय, एलइडी लाइट, हर सीट के नीचे चार्जिंग प्वाइंट, हर सीट के नीचे रीडिंग लाइट, इंटेलिजेंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर के उपयोग से ट्रेन में चढने की सुविधा, उनके लिए अलग से शौचालय, सीसीटीवी, फायर फाइटिंग सिस्टम, स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजा जैसी सुविधाएं हैं।

करदाता दो साल के भीतर दाखिल कर सकते हैं अद्यतन आयकर रिटर्न

- राज्य सरकारों के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के अंशदान पर कर कटौती सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत की गई
- वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लेन-देन से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर देना होगा

नईदिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए घोषणा की कि सरकार ने एक नया प्रस्ताव किया है जिसके तहत करदाता अतिरिक्त कर की अदायगी करने पर एक 'अद्यतन रिटर्न' दाखिल कर सकते हैं। इस अद्यतन रिटर्न को संबंधित आकलन वर्ष के समापन से लेकर अगले दो वर्षों के भीतर दाखिल करना होगा। उन्होंने

कहा कि इससे करदाताओं को कर भुगतान के लिए अपनी आय का सटीक आकलन करने में हुई किसी चूक या त्रुटि को दूर करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि मौजूदा समय में यदि आयकर विभाग को यह पता चलता है कि किसी करदाता ने अपनी कुछ आय को अपने रिटर्न में नहीं दर्शाया है तो वैसी स्थिति में इस पूरे मामले को निपटाने के लिए उसे एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हालांकि, इस नए प्रस्ताव के तहत अब करदाताओं पर भरोसा किया गया है। उन्होंने कहा, 'यह स्वैच्छिक कर अनुपालन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।'

दिव्यांगजनों को कर राहत- वर्तमान कानून के तहत किसी दिव्यांगजन के लिए बीमा योजना लेने वाले माता-पिता या अभिभावक को कर कटौती की अनुमति तभी दी जाती है जब संबंधित ग्राहक की मृत्यु होने पर उस दिव्यांगजन को एकमुश्त भुगतान या वार्षिकी उपलब्ध हो जाती है। चूंकि आश्रित दिव्यांगजनों को यहां तक कि अपने माता-पिता/अभिभावक के जीवन काल के दौरान ही एकमुश्त राशि या वार्षिकी के भुगतान की जरूरत पड़ सकती है, अत: इस तरह की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए श्रीमती सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार के नए प्रस्ताव के तहत आश्रित दिव्यांगजन को अपने माता-पिता/अभिभावक के जीवन काल के दौरान भी वार्षिकी और एकमुश्त राशि का भुगतान किया जा सकता है। हालांकि, ऐसा तभी होगा जब संबंधित ग्राहक की आयु 60 साल हो जाएगी।

राज्य और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता- वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों को मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा लाभों को बढ़ाने और इन्हें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समतुल्य करने के लिए बजट में राज्य सरकारों के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के अंशदान पर कर कटौती सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।

वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर कर लगाने के लिए योजना- वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों का लेन-देन काफी ज्यादा बढ़ जाने का उल्लेख करते हुए श्रीमती सीतारमण ने घोषणा की कि 'किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर होने वाली किसी भी आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर देना होगा।' उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अधिग्रहण की लागत को छोड़ इस तरह की आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते पर किसी भी कर कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर होने वाले नुकसान का समायोजन किसी भी अन्य आय से नहीं की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह के सौदे के विवरण को दर्ज करने के लिए सरकार वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर इससे जुड़ी राशि के एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का भी प्रावधान करेगी। हालांकि, इसके लिए एक मौद्रिक सीमा तय की गई है और उससे ज्यादा राशि होने पर ही स्रोत पर कर कटौती की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति को उपहार के रूप में देने पर भी कर लगाने का प्रस्ताव है। यह कर उपहार लेने वाले को देना होगा।

मुकदमेबाजी का प्रबंधन- श्रीमती सीतारमण ने कहा कि 'समान तरह के मुद्दों पर अपील दाखिल करने में काफी समय और संसाधन खर्च हो जाते हैं।' सरकार की सुव्यवस्थित मुकदमेबाजी प्रबंधन नीति को आगे बढ़ाने और करदाताओं एवं विभाग के बीच बार-बार होने वाली मुकदमेबाजी में कमी करने के लिए सरकार इस आशय का प्रावधान करेगी कि किसी करदाता के मामले में कोई कानूनी मुद्दा यदि ठीक उस कानूनी मुद्दे जैसा ही होता है जो किसी मामले में क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में की गई अपील के तहत लंबित है, तो विभाग द्वारा इस करदाता के मामले में आगे अपील करने को तब तक के लिए टाल दिया जाएगा जब तक कि इस तरह के कानूनी मुद्दे पर संबंधित क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अपना फैसला नहीं सुना देता है।